दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

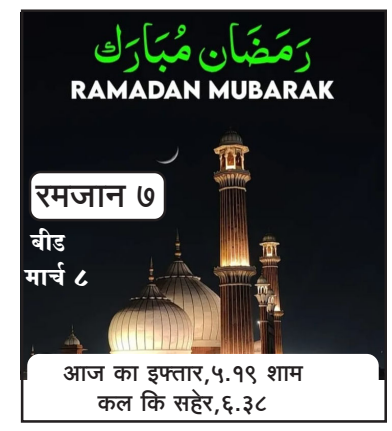

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२१५ वा | शनिवार ८ मार्च २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रुपये | पन्ने - ४

शिक्षा विभाग के फैसले पर उठे सवाल

सख़्त गर्मी में २५ अप्रेल से इम्तिहानात

शिक्षक और अभिभावक नाराज

पूणे , ७ मार्च (मोहम्मद मुस्लिम कबीर कि रिपोर्ट)

महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष वार्षिक परीक्षाओं को २५ अप्रैल तक कराने का फैसला शिक्षकों और अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस निर्णय पर अभिभावकों और शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है और इसे अव्यवहारिक बताया है।

पिछले सालों की तुलना में बदला गया परीक्षा कार्यक्रम

हर साल प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की परीक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरी कर ली जाती थीं और १५ अप्रैल तक परिणाम तैयार कर लिया जाता था। इससे शिक्षकों को रिजल्ट तैयार करने, ग्रेडिंग और अन्य औपचारिकताओं के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। लेकिन इस बार २५ अप्रैल तक परीक्षा कराने के निर्णय से शिक्षकों को महज ५ दिन में रिजल्ट तैयार करना होगा, जो कि बेहद कठिन है।

झ-ढ और अन्य परीक्षाओं के साथ नई चुनौतियां

इस साल वार्षिक परीक्षा के साथ-साथ समेटिव असेसमेंट-२ और झ-ढ टेस्ट को भी शामिल किया गया है। झ-ढ परीक्षा में उर्दू/मराठी, अंग्रेज़ी और गणित विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। यह परीक्षा कक्षा ३ से ९ तक के छात्रों के लिए अनिवार्य है, जिससे शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

यदि शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार परीक्षाएं २५ अप्रैल तक पूरी होती हैं, तो १ मई को रिजल्ट घोषित करने के लिए शिक्षकों को केवल ५ दिन मिलेंगे। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, ग्रेडिंग, ऑनलाइन झ-ढ टेस्ट नंबर दर्ज करने और रिजल्ट शीट तैयार करने में मुश्किलें आएंगी।

गर्मी और पानी की समस्या भी बड़ी चुनौती

अभिभावकों और शिक्षकों ने यह भी चिंता जताई है कि १५ अप्रैल के बाद राज्य में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी हो जाती है और कई अभिभावक मजदूरी के लिए पलायन करने लगते हैं। इससे बच्चों की उपस्थिति पर सीधा असर पड़ेगा और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में भी दिक्कत होगी।

शिक्षकों को छात्रों को स्कूल तक बुलाने के लिए घर-घर जाना पड़ेगा, जिससे उन पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ेगा। गर्मी के कारण छात्रों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

शिक्षक संघटनों की मांग - शिक्षा विभाग पुनर्विचार करे

शिक्षक संघटनों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले वर्षों की तरह परीक्षा का समय अप्रैल के पहले पखवाड़े में रखा जाए, ताकि शिक्षकों और छात्रों को अनावश्यक दबाव से बचाया जा सके।

मुख्य मांगें:

वार्षिक परीक्षा १५ अप्रैल तक पूरी होनी चाहिए। रिजल्ट तैयार करने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय दिया जाए।

गर्मी और पानी की समस्या को देखते हुए परीक्षा शेड्यूल में बदलाव किया जाए। झ-ढ और अन्य परीक्षाओं को वार्षिक परीक्षा से अलग समय पर लिया जाए।

शिक्षकों और अभिभावकों का कहना है कि अगर इस फैसले पर जल्द पुनर्विचार नहीं किया गया, तो छात्रों और शिक्षकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

महाराष्ट्र में सस्ती होगी बिजली, १.५ करोड़ परिवारों को मिलेगी राहत-फडणवीस

पांच साल में बिजली दरों में २४% की कमी, स्मार्ट मीटर पर १०% छूट

मुंबई, ७ मार्च (अज़ीज़ इजाज़) - महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में बिजली दरों में २४% की कमी की जाएगी, जबकि पिछले २० वर्षों में बिजली दरों में औसतन ९% की वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत १.३० करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले २० लाख मकानों में भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे।बिजली के बिलों से मिलेगी पूरी राहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, राज्य में ७०% घरेलू उपभोक्ता (लगभग १.५ करोड़ परिवार) जो हर महीने ० से १०० यूनिट बिजली की खपत करते हैं, अपने घरों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली के बिलों से पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे।

२०३० तक ५२% बिजली गैर-पारंपरिक स्रोतों से आएगी

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि २०३० तक राज्य में ५२% बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली की कीमतों में हर साल ९% की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन सरकार ने १.१३ लाख करोड़ रुपये की बचत करते हुए पांच साल में बिजली दरों को २४% तक कम करने का फैसला किया है। इसके अलावा, घरेलू उपभोक्ताओं को ९५% तक राहत दी जाएगी और स्मार्ट मीटर लगाने पर दिन के समय बिजली के बिल में १०% छूट मिलेगी।

१०० से ३०० यूनिट उपभोक्ताओं के लिए १७% की कमी

जो उपभोक्ता १०० से ३०० यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उनके लिए बिजली दरों में १७% की कटौती की जाएगी। इससे राज्य के ९५% घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

किसानों को ७५,००० करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल में राहत

सरकार ने किसानों के ७५,००० करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों को धीरे-धीरे चुकाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, सरकार महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (महावितरण) को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही है। अगर यह योजना लागू होती है, तो महावितरण देश की पहली स्टॉक लिस्टेड बिजली वितरण कंपनी बन जाएगी।

महाराष्ट्र बनेगा देश का सबसे विकसित राज्य मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र उद्योग, कृषि, सेवा और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में देश में सबसे ज्यादा आधारभूत संरचना का विकास हुआ है और इसे और भी मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं लड़कियों की शिक्षा पर मिलने वाली ५०% छूट को बढ़ाकर १००% किया जाएगा। राज्य में रिकॉर्ड ११.२१ लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद हुई। नार-पार, गरना और वेणगंगा से नलगंगा नदी को जोड़ने की योजना को मंजूरी। डेवोस सम्मेलन में १५.७० लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत २० लाख मकानों को मंजूरी। गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अब सीमेंट-कंक्रीट से बनाई जाएंगी। नागपुर से गोवा तक शक्ति पीठ हाईवे' का निर्माण होगा। साइबर सिक्योरिटी सेंटर को महामंडल में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए ताकि महाराष्ट्र को देश का सबसे बेहतर राज्य बनाया जा सके।

मुंबई में १ से ४ मई को W-VES सम्मेलन का आयोजन- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में होगा आयोजन

मुंबई, ७ मार्च: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक ऑडियो-विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (थ-तएड) का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन १ से ४ मई २०२५ के बीच जीओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति, नीति-निर्माता और इनोवेटर्स भाग लेंगे। इसमें 'मीडिया और मनोरंजन उद्योग की संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसको लेकर सभी विभागों को समन्वय के साथ तैयारियां करने के निर्देश मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने दिए हैं।

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की अध्यक्षता में मंत्रालय में इस सम्मेलन की आयोजन बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, सह सचिव संजीव शंकर, सी. सेंथिल राजन, अजय नागभूषण एम.एन., मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगराणी, सांस्कृतिक कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे, उद्योग विभाग के सचिव पी. अन्बलगन, एमआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, उद्योग आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, फिल्म डिवीजन की प्रबंध निदेशक स्वाति पाटील, आईटी विभाग के निदेशक अनिल भंडारी, विशेष पुलिस महानिदेशक देवेन भारती, मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भारतीय मीडिया उद्योग को मिलेगी वैश्विक पहचान

बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को वैश्विक कंटेंट हब बनाना, भारतीय आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा (खपींशश्रश्रशलीींरश्र झीेशिीीं) की समृद्ध प्रणाली तैयार करना और भारतीय संस्कृति व भाषाओं की विविधता को बनाए रखना है।

इसके अलावा, भारत की मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत करना, वैश्विक निवेश आकर्षित करना, अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाना और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना भी इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहेगा।

इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, भारतीय उद्योग जगत के नेता, ट्रेड यूनियन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप कंपनियां, प्रौद्योगिकी कंपनियां, फिल्म निर्माण कंपनियां, फिल्म फंडिंग संस्थाएं, निर्देशक, निर्माता, कंटेंट क्रिएटर, पटकथा लेखक और उद्योग विशेषज्ञ भाग लेंगे। मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नए अवसर मिलेंगे

जाजू ने कहा कि यह सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक वैश्विक मंच होगा।

उन्होंने बताया कि २०२४ में वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग का मूल्य लगभग २.९६ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसे में थ-तएड सम्मेलन भारत में इस क्षेत्र को और अधिक गति प्रदान करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग २०२९ तक ५०० अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। थ-तएड सम्मेलन इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने, नीतिगत सुधारों को प्रोत्साहित करने और नवाचारों को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।

राज्यस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कहा कि इस वैश्विक सम्मेलन की तैयारियों के लिए राज्यस्तरीय समिति गठित की जाएगी।

सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और कार्यक्रम की सूक्ष्म योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि - सम्मेलन का विस्तृत कार्यक्रम, आगंतुकों का आगमन और प्रस्थान, प्रचार-प्रसार, मेहमानों का आतिथ्य, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सभी पहलुओं की सही योजना बनाई जानी चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि थ-तएड सम्मेलन भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए ऐतिहासिक अवसर साबित होगा, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकेगा।

८ लाख करोड़ के कर्ज के बावजूद सरकार की तिजोरी पर डाका-अंबादास दानवे

जमीर काज़ी । मुंबई, ८ मार्च - महाराष्ट्र पर ८ लाख करोड़ रुपये का कर्ज होने के बावजूद सरकार द्वारा पेश की गई अनुपूरक मांगों के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लगाया।

वह शुक्रवार को विधान परिषद में सरकार की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कार्यान्वयन नहीं होता।

लोकप्रिय योजनाओं की आड़ में कर्ज बढ़ाने का आरोप

दानवे ने राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के लिए सरकार से लोकलुभावन योजनाओं के पीछे न भागने की अपील की। उन्होंने सरकार की नीतियों, अनुपूरक मांगों में असमानता, लंबित परियोजनाओं और निधि आवंटन में गड़बड़ी पर कड़ी आलोचना की।

जलसंपदा विभाग में २७,००० करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, लेकिन अब तक केवल १४,००० करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जीवन मिशन के तहत ९४५ योजनाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन २९,००० करोड़ रुपये की मांग के बावजूद बहुत कम फंड आवंटित किया गया। सरपंचों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की गई, लेकिन अभी तक उनके खातों में पैसा जमा नहीं हुआ। परभणी जिले के मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ा है। समान शिक्षा अधिकार कानून के तहत मुफ्त शिक्षा की योजना है, लेकिन इसके लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया। सावित्रीबाई फुले स्मारक के लिए १०,००० करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई थी, लेकिन एक भी ईंट नहीं रखी गई। पुलिस कर्मचारियों के लिए निवास की समस्या अभी भी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा २०२२ में घोषित 'हर घर छत' योजना के तहत अब तक १०% से भी कम मकानों का निर्माण हुआ है, और लाभार्थियों की राशि भी घटा दी गई है।

दिव्यांगों के लिए मुफ्त स्कूटर योजना: आज सामाजिक न्याय भवन में निकलेगा लकी ड्रॉ'

बीड़, ७ मार्च (प्रतिनिधि) - बीड़ जिला परिषद के जिला समाजकल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को मुफ्त तीन पहिया स्कूटर वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत ५४ दिव्यांगों को स्कूटर देने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि १३२८ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए, लकी ड्रॉ निकालकर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। यह लकी ड्रॉ ८ मार्च को सुबह १०:३० बजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, नगर रोड, बीड़ में आयोजित किया जाएगा।

१००% अनुदान पर दी जाएगी स्कूटर

जिला समाजकल्याण विभाग वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में ५% दिव्यांग निधि से १००% अनुदान के तहत अस्थिव्यंग (हड्डी संबंधी दिव्यांगता) वर्ग के लिए स्कूटर विद अडॉप्टर योजना चला रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों ने अपने तालुका पंचायत समिति के गटविकास अधिकारी के पास आवेदन किए थे।

११ तालुकों से १३२८ आवेदन, लेकिन सिर्फ ५४ को मिलेगा लाभ

बीड़ जिले के ११ तालुकों से कुल १३२८ आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन सिर्फ ५४ दिव्यांगों को ही तीन पहिया स्कूटर विद अडॉप्टर देने का लक्ष्य तय किया गया है। चूंकि आवेदन निर्धारित संख्या से अधिक हैं, इसलिए लकी ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

लकी ड्रॉ इन-कैमरा, सभी आवेदकों से उपस्थित रहने की अपील

जिला समाजकल्याण अधिकारी एस. एन. मेश्राम ने सभी आवेदकों से लकी ड्रॉ कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की है। यह ड्रॉ इन-कैमरा आयोजित किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

ऊर्दू माध्यमचा शिक्षकांच्या नियुक्त्या ऊर्दू माध्यम मध्ये करा आमदार ईद्रीस नायकवडी

मुंबईः संवादाता

अर्थ संकल्पीय अधिवेशन २०२५ च्या चौथ्या दिवशी प्रश्न क्रमांक ५०५ वर विधान परिषदेत शिक्षकांचे प्रश्न उपस्थितीत करतांना आमदार इद्रीस नाईकवाडी यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना मुद्दा उपस्थितीत केला की पवित्र पोर्टल माध्यमातून शिक्षक भरती काढली व शिक्षक भरण्यात आले.शिक्षक भरतीची जाहीरात काढतांना कोणत्या माध्यमातून किती जागा रिक्त आहेत यांची माहिती ना देता सरळ भरती करण्यात आली.मध्ये शिक्षक भरती करतांना किती पदे रिक्त आहेत ही माहिती दिली नाही .ही चुक शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली ही चुक शासनाने मान्य करुन दुरूस्त करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि दुसर्या टप्प्यात दुरुस्त करू असे म्हटले परंतु लगेच दुरूस्त करुन विविध भाषांच्या शिक्षकांना न्याय द्या यात ऊर्दू माध्यम मध्ये इंग्रजी व मराठी भाषा शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आले आहे तसे ना करता ऊर्दू माध्यम शिकविण्यासाठी ऊर्दू भाषीक शिक्षक दया .व मराठी कन्नड व विविध इतर भाषीक शाळेत त्यामाध्यमाचे शिक्षक दया.अशी मागणी आमदार इद्रीस नाईकवाडी यांनी विधानपरिषदेत केली तसेच सोलापूर व सांगली जिल्हा परिषदेत शिक्षक भरती करतांना यादीत विविध भाषा कन्नड व ऊर्दू माध्यमांचा शाळेना मराठी माध्यमाचे शिक्षक भरती केली आहे.कन्नड ऊर्दू भाषेचा ज्ञान नसलेल्या शिक्षकांना ऊर्दू व कन्नड शाळेना मराठी भाषा शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आले आहे.नविन जाहीरात काढुन चुकांची दुरुस्ती करण्यात यावी विविध भाषेचा माध्यमाच्या शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी असे मुद्दा आमदार इद्रीस नाईकवाडी यांनी उपस्थितीत केला तसेच शालेय शिक्षण मंत्री दादा साहेब भुसे यांनी आश्वासन दिले की लवकरात लवकर कारवाई करु

पत्रकार शेख रिजवान को रयत सामाजिक प्रतिष्ठान' का राज्यस्तरीय समाजरत्न पुरस्कार घोषित

९ मार्च को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन में होगा पुरस्कार वितरण समारोह

बीड़, ७ मार्च (प्रतिनिधि) – रयत सामाजिक प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य हर साल समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाजसेवकों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित करता है। इस वर्ष प्रतिष्ठान ने समाजरत्न पुरस्कार' पत्रकार शेख रिजवान (संपादक, दिव्य आधार) को प्रदान करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार समारोह ९ मार्च को दोपहर १२ बजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बीड़ में आयोजित किया जाएगा।

समाजसेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान

रयत सामाजिक प्रतिष्ठान पिछले तीन वर्षों से सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर रहा है। कोरोना काल में जरूरतमंदों की सहायता, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर आयोजन और समाजसेवा के अन्य कार्यों में योगदान देने वालों को यह प्रतिष्ठान सम्मानित करता है।

इन समाजसेवकों को भी मिलेगा पुरस्कार इस वर्ष के पुरस्कारों की सूची में बीड़ शहर के सुशील खटोड, भागवत वैद्य समेत जिला एवं अन्य जिलों के कई प्रतिष्ठित समाजसेवकों के नाम शामिल हैं।

सभी मित्रों और शुभचिंतकों से उपस्थिति की अपील पुरस्कार वितरण समारोह में सम्माननीय अतिथियों की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। रयत सामाजिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आर. जी. माने ने सभी मित्रों, शुभचिंतकों और समाजसेवकों से इस समारोह में सहभागी बनने की अपील की है।

बीड जिले में मनरेगा के कुशल मजदूरी भुगतान जल्द होंगे जारी-कुंडलिक खांडे

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने दिए अधिकारियों को आदेश

बीड (प्रतिनिधि): बीड जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत २०२१ से २०२५ तक ९८४ ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों के कुशल मजदूरी भुगतान अब तक लंबित हैं। इस मुद्दे को लेकर सरपंच-उपसरपंच संघटना के संस्थापक अध्यक्ष कुंडलिक खांडे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए रोहयो (रोजगार हमी योजना) विभाग के सचिवों को आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में कुंडलिक खांडे ने कहा कि मनरेगा के तहत कुशल मजदूरी के भुगतान जल्द ही किए जाएंगे।

मनरेगा के तहत ५ वर्षों से लंबित हैं भुगतान

केंद्र सरकार ने सुवर्ण जयंती रोजगार गारंटी योजना को समाप्त कर २००८ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) शुरू की। २०१० से इस योजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत लाभकारी योजनाएं चलाना और सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

बीड जिले की ९८४ ग्राम पंचायतों में पिछले ५ वर्षों से कुशल मजदूरी के भुगतान लंबित हैं। इस कारण किसानों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों को गंभीर वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरपंच-उपसरपंच संघटना के अध्यक्ष कुंडलिक खांडे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर लंबित भुगतान जारी करने का अनुरोध किया। इस पर उपमुख्यमंत्री शिंदे ने रोजगार हमी योजना के सचिवों को जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया।

कुंडलिक खांडे ने कहा कि इस प्रयास से जल्द ही लंबित देयकों का भुगतान शुरू होगा और किसानों व सरपंचों को राहत मिलेगी।

प्रोजेक्ट रोकने के लिए मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विरोधियों पर हमला

रिपोर्ट: जमीर काज़ी

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार समन्वय से चल रही है और वह विकास कार्यों में बाधा डालने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैं कोई उद्धव ठाकरे नहीं हूं जो प्रोजेक्ट को रोक दूं।

विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा, आजकल मीडिया में क्वालिटी की खबरें नहीं हैं और न ही विपक्ष से क्वालिटी की आलोचना हो रही है। जो भी होता है, फडणवीस ने शिंदे के प्रोजेक्ट को रोका, यह एक पेड न्यूज़ बन जाता है। पहले यह समझ लीजिए, प्रोजेक्ट रोकने के लिए मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं।

उन्होंने आगे कहा, हम तीनों (शिंदे-फडणवीस-अजित पवार) ने तय किया है कि जो भी राज्य के हित में होगा, वह पूरा किया जाएगा। यदि किसी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी मिलेगी, तो उस पर चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का सम्मान करने वाली सरकार हैं

फडणवीस ने ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए कहा, हमने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों से प्रमाण पत्र नहीं मांगे। हमारा काम गढ़-किलों से अतिक्रमण हटाने और १२ किलों को हेरिटेज घोषित करने का है।

दावोस में हुए समझौते पर विपक्ष की शंकाएं गलत

विपक्ष द्वारा दावोस में हुए निवेश समझौतों पर उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमने वहां ६३ एमओयू साइन किए, जिनमें से आधे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। जयंतराव (जयंत पाटिल), आपका प्रॉब्लम यह है कि आप गलत समय पर गलत लोगों के साथ गलत बातें कहते हैं। रोहित पवार या वरुण (राजनीतिक नए चेहरे) यदि शंका करें तो समझ में आता है, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ नेता को महाराष्ट्र की निवेश नीति पर संदेह नहीं करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, २०२२ में जब आदित्य ठाकरे दावोस गए थे, तब उन्होंने ८०,००० करोड़ रुपये के समझौते किए थे, जो भारतीय कंपनियों के साथ थे। महाराष्ट्र को लेकर दावोस में हमेशा चर्चा होती है, इसलिए इसे संकुचित दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है।

एचएसआरपी नंबर प्लेट के रेट्स को लेकर कोई हेराफेरी नहीं

फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि एचएसआरपी (हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट) के रेट महाराष्ट्र में तय करते समय अन्य राज्यों के दरों की तुलना की गई है। उन्होंने बताया कि –

दुपहिया वाहनों के लिए रेट ४२० से ४८० रुपये के बीच हैं, जबकि महाराष्ट्र में यह ४५० रुपये है।

तीन पहिया वाहनों के लिए अन्य राज्यों में यह ४५० से ५५० रुपये के बीच है, जबकि महाराष्ट्र में ५०० रुपये है।

चार पहिया वाहनों के लिए अन्य राज्यों में ८०० रुपये तक शुल्क है, जबकि महाराष्ट्र में यह ७४५ रुपये है।

भारी वाहनों के लिए यह ६९० से ८०० रुपये के बीच है, जबकि महाराष्ट्र में यह ७४५ रुपये रखा गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक विशेष कमेटी बनाकर इन दरों का निर्धारण किया गया है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

हम समन्वय से चलने वाली सरकार हैं मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार समन्वय से चलती है और सभी विभागों के मंत्री स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं। लेकिन यदि किसी मंत्री ने कोई फैसला लिया तो मीडिया में खबर आ जाती है कि 'फडणवीस ने शिंदे के प्रोजेक्ट को रोका'। उन्होंने कहा, हमने जनता का भारी समर्थन पाया है और यह समर्थन हमें संविधान के अनुसार काम करने का निर्देश देता है।

हम विकास कार्यों में बाधा डालने वालों में से नहीं हैं

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की कार्यशैली को स्पष्ट करते हुए कहा, हम विकास करने वाले लोग हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को रोकने वाले नहीं हैं। विपक्ष की आलोचना पर तंज कसते हुए उन्होंने सुरेश भट की एक प्रसिद्ध ग़ज़ल की पंक्तियाँ सुनाईं –

साऱ्यांची शंकांची अशी मागू नको उत्तरे, असताच शंकेखोर त्यांचे कधी झाले बरे...

हम महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विपक्ष को महाराष्ट्र की विकास योजनाओं पर अनावश्यक शंका नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकास कार्यों में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे नेतृत्व में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ठोस योजनाओं पर काम हो रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता।

यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार डॉ. राणी बंग और डॉ. अभय बंग को प्रदान किया जाएगा

मुंबई, विशेष प्रतिनिधि: समाज और चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर आदिवासी समाज के जीवन में बदलाव लाने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक दंपति डॉ. राणी बंग और डॉ. अभय बंग को साल २०२४ के 'यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा।

यह पुरस्कार यशवंतराव चव्हाण सेंटर द्वारा हर साल दिया जाता है, और इस वर्ष यह सम्मान १२ मार्च को शाम ५ बजे प्रतिष्ठान के अध्यक्ष शरद पवार के हाथों प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को मिलता है सम्मान

यशवंतराव चव्हाण सेंटर राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों और संस्थानों को यह पुरस्कार प्रदान करता है।

इस पुरस्कार के तहत ५ लाख रुपये की धनराशि और सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है।

डॉ. राणी बंग और डॉ. अभय बंग ने सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य करते हुए आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इसी कार्य को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष 'यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार' की घोषणा की गई है।

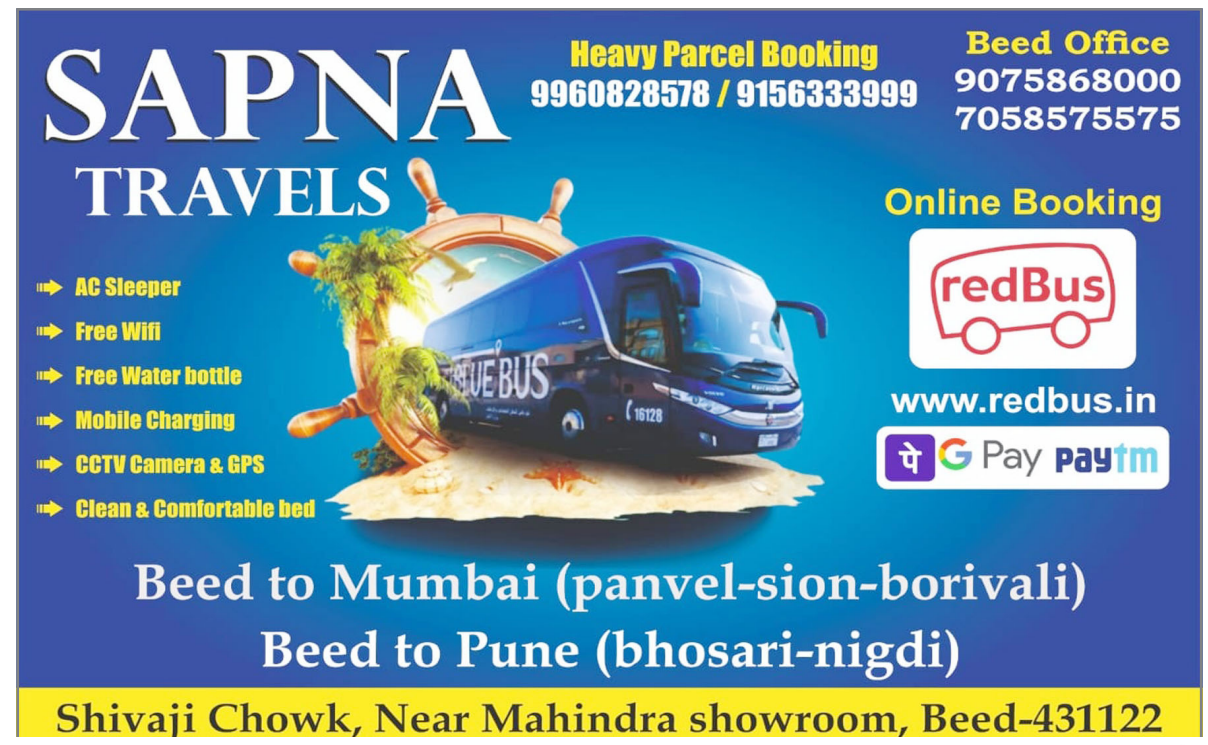

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com